



www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रु.

वर्ष: 19

अंक: 112

आगरा, शनिवार 10 अक्टूबर 2026

एसआईआर विवाद: सत्ता पक्ष का जोर जनता के भरोसे पर, विपक्ष सड़क पर

नई दिल्ली(ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ खेमा विपक्ष से ज्यादा आम जनता के बीच भरोसे को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल दिल्ली की गहमागहमी से ज्यादा अपने जमीनी कार्यक्रमों और अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सत्ता पक्ष सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभाव की काट के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साध रहा है। संसद के मॉनसून सत्र से ही विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। पहले छात्र आंदोलन और जेन-जी की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए आंदोलनकारियों की माँगें मानकर उसे समाप्त किया था। सरकार का मानना है कि इससे विपक्ष के मंसूबे पूरे नहीं हो सके थे। अब विपक्ष ने एसआईआर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना



साधा हुआ है। दिल्ली में बीते तीन दिनों से विपक्ष, खासकर कांग्रेस का नेतृत्व सड़कों पर है। भाजपा और विपक्ष के बीच तीखे शब्दबाण चलाए जा रहे हैं। भाजपा ने भी अपने प्रवक्ताओं और

प्रमुख नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जो विपक्षी आरोपों का जवाब देने के साथ पलटवार भी कर रहे हैं। भाजपा के एक महासचिव ने कहा है कि विपक्ष को प्रदर्शन करने का हक

है, पर जिस तरह वह संबैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है, वह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा और राजग की एकजुटता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। नेता चिराग पासवान ने भी कहा है कि अगर विपक्ष को अब भी कुछ शंकाएं हैं तो आयोग से सीधी बात करनी चाहिए।

शक के आधार पर किसी को बांग्लादेशी बताकर नहीं निकाल सकती सरकार

कोलकाता(ए)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार किसी को केवल शक के आधार पर बांग्लादेशी बताकर देश से नहीं निकाल सकती है। जस्टिस सीपत भट्टाचार्य की कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। यह टिप्पणी मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति की हिरासत और उसे देश से बाहर भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को कुछ पड़ोसियों के बयानों से पैदा हुए शक के आधार पर 8 अगस्त से हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने फरिसेर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) द्वारा उनके पति को देश से बाहर भेजने और हिरासत में लेने के आदेश को

चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में पत्नी को हिरासत में नहीं लिया गया है।



स्पष्ट और योग्य प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया? सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ दावों के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे तय की जा सकती है? उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जज ने एक और अहम सवाल उठाया, 1970 के दशक से कितने लोगों ने सीमा पार की है? क्या उन सभी को वापस भेजना संभव है?

याचिकाकर्ता के वकील रबीउल इस्लाम ने सुनवाई के दौरान कहा, भरे मुवक्किल को दो महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। उन्हें कुछ पड़ोसियों के बयानों से पैदा हुए शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। इस पर जस्टिस भट्टाचार्य ने सरकार के वकील से सवाल किया कि उस व्यक्ति को दो महीने तक हिरासत में क्यों रखा गया? उन्होंने यह भी पूछा कि अधिकारियों ने उसकी नागरिकता तय करने के लिए

इन टिप्पणियों के साथ, उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया ताकि इसे सही ढंग से सुना जा सके, जो इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे सुनवाई कर सके। यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर अपनी नागरिकता साबित करने और देश से निकाले जाने का सामना करना पड़ रहा है।

भारत की बड़ी तैयारी- भारतीय टैंकों पर लगेंगे ड्रोन रोधी कवच

नई दिल्ली(ए)। आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और सुसाइड ड्रोन टैंकों समेत भारी सैन्य वाहनों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसी बदलते खतरे को देखते हुए भारत ने अपने मौजूदा मुख्य युद्धक टैंकों को काउंटर-ड्रोन सिस्टम से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशनल टैंकों पर काउंटर-यूएस यानी ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने के लिए खरीद और रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी है।इस योजना के तहत भारतीय सेना के प्रमुख टैंक बेड़े में शामिल टी-90 भीएम, टी-72 अजेय और स्वदेशी अर्जुन को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। रक्षा सचिव

सार्वजनिक नहीं की गई है। हाल के युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के साथ-साथ सीधे हमले के

आमतौर पर ड्रोन का पता लगाने, उसकी पहचान करने, ट्रैक करने और खतरे को निष्क्रिय करने की क्षमता पर आधारित होते हैं। इसके लिए छोटे रडार, कैमरा और अन्य सेंसर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खतरे को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे सॉफ्ट-किल उपायों के साथ ड्रोन को भौतिक रूप से नष्ट करने वाले हार्ड-किल विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारतीय टैंकों पर इनमें से कौन सी तकनीक या संयोजन लगाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लिए तेजी से बढ़ा है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन टैंकों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और उन पर विस्फोटक गिराने या लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए हमला कर सकते हैं। आकार छोटा होने और कम लागत के कारण बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल भी संभव है, जिससे पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों पर दबाव बढ़ता है। काउंटर-यूएसएस सिस्टम

मौजूदा टैंकों में ऐसी प्रणाली जोड़ना तकनीकी चुनौती भी होगी। रेट्रोफिटिंग के दौरान सिस्टम का वजन, आकार, अतिरिक्त बिजली की जरूरत और टैंक की गतिशीलता जैसे पहलुओं का ध्यान रखा होगा। साथ ही मुख्य तोप और अन्य युद्ध प्रणालियों के संचालन पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए।



20 बागी सांसदों की बढ़ी मुश्किलें, नोटिस का जवाब देने की समयसीमा खत्म

नई दिल्ली(ए)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) से गठबंधन करने वाले 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस का जवाब देने की दो सप्ताह की समयसीमा हाल ही में समाप्त हो गई, जिसके बाद इन सांसदों ने एक बार फिर दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। इसी बीच, इन बागी सांसदों की कोलकाता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में केवल आधे ही सदस्य शामिल हुए, जिससे उनके खेमे में आंतरिक फूट की अटकलें तेज हो गई हैं।

इन 20 सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की गई है, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। शिकायतें मुख्य रूप से टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के साथ उनके गठबंधन को लेकर हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद सांसदों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए थे। रिपोर्टों के अनुसार, सांसदों ने सितंबर की शुरुआत में चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन उन्हें केवल दो सप्ताह की मोहलत मिली। अब, समयसीमा समाप्त होने के बाद, यह चौथी बार है जब सांसदों ने इस लंबे कानूनी और राजनीतिक विवाद में अतिरिक्त समय की मांग की है। कोलकाता में बागी सांसदों की बुलाई गई बैठक में 20 में से केवल 10 सांसद ही शामिल हो पाए। वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य आगे की कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना था, लेकिन आधे सदस्यों की अनुपस्थिति ने इसमें नया मोड़ ला दिया। काकोली घोष दस्तोदार, सायोनो घोष, यूसुफ पठन, माला रॉय, जून मालिया, पार्थ भौमिक, मिताली बाग, कालीपद सोरेन, देव और असीत माल जैसे प्रमुख नाम बैठक से नदारद रहे, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या बागी सांसदों के भीतर ही कोई नई बग़ावत पनप रही है। वहीं, सुदीप बंद्योपाध्याय के अलावा अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, बापी हलदर, रचना बनर्जी और अरुण चक्रवर्ती बैठक में मौजूद रहे।

हालांकि, बैठक में शामिल सांसदों ने अनुपस्थित सदस्यों को लेकर किसी भी तरह के मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ सांसद विदेश में हैं, कुछ के परिवार में परेशानी है, जबकि कुछ अन्य बैठकों में व्यस्त हैं। सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं, इस पर नजर रखना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं, शर्मिला सरकार ने भी स्पष्ट किया कि बैठक में नहीं आ पाने वाले सांसदों के साथ किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। सांसद रचना बनर्जी ने इस आयोजन को दुर्गा पूजा से पहले एक सामान्य मिलन-जुलन कार्यक्रम बताया, जिसमें सभी का मिलना जरूरी था क्योंकि संसद के बाद वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हो जाते हैं।

भारतीय डाक ने पीढ़ियों से देश के करोड़ों लोगों को एक-दूसरे से जोड़े रखा

नई दिल्ली, (ए)। विश्व डाक दिवस पर कई मुख्यमंत्री समेत नेताओं ने प्रदेशवासियों और डाक कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक में कहा, विश्व की सबसे सशक्त, व्यापक व विश्वसनीय डाक व्यवस्था भारतीय डाक तंत्र के सभी समर्पित डाक कर्मियों तथा प्रदेशवासियों को विश्व डाक दिवस की शुभकामनाएं दीं। देश के हर कोने, हर वर्ग और हर नागरिक को विश्वास, संवेदना एवं सेवा के सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने वाले डाक परिवार का हार्दिक अभिनंदन।

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा- समस्त प्रदेशवासियों को विश्व डाक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! देश के कोने-कोने तक लोगों को जोड़ने और आवश्यक संदेशों व सेवाओं को पहुंचाने में डाक व्यवस्था ने सालों से अहम भूमिका निभाई है। बदलते समय के साथ नए आयामों को अपनाने हुए डाक विभाग आज भी जनसेवा और संपर्क का सशक्त जरिया बना हुआ है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था, भारतीय डाक ने पीढ़ियों से देश के करोड़ों लोगों को एक-दूसरे से जोड़े रखा है। कभी अपनों की चिट्ठियां, कभी खुशियों के संदेश और आज घर-घर तक पहुंचती आधुनिक सेवाएं। भारतीय डाक सेवा और विश्वास की अनूठी पहचान है। विश्व डाक दिवस पर पोस्ट ऑफिस परिवार के सभी समर्पित डाक कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स में लिखा- संचार और सेवा के जरिए देश को जोड़ने वाले सभी डाककर्मियों को विश्व डाक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश के कोने-कोने तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने में डाककर्मियों की भूमिका सदैव अहम रही है।



नई दिल्ली(ए)। भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई गति मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी विमान इंजन निर्माता जीई एयरोस्पेस ने तेजस के लिए चार एफ404-आईएन20 इंजन की आपूर्ति हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को की है। इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण तेजस एमके1ए कार्यक्रम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब उत्पादन और डिलीवरी में तेजी आने की संभावना है।सितंबर 2026 में चार इंजन एचएएल को भेजे गए। इससे पहले अगस्त में तीन इंजन की आपूर्ति की गई थी। कंपनी जून से दिसंबर 2026 के बीच कुल 20 एफ404-आईएन20 इंजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। जीई एयरोस्पेस के मुताबिक, वह भारतीय वायुसेना और एचएएल के साथ मिलकर तेजस कार्यक्रम के लिए जरूरी इंजन की आपूर्ति पर ध्यान

केंद्रित कर रहा है। एचएएल ने तेजस एमके1ए के लिए 2021 में जीई से 99 एफ404-आईएन20 इंजनों का ऑर्डर दिया था। जीई के अनुसार, अतिरिक्त ऑर्डर मिलने के समय इस इंजन की उत्पादन लाइन करीब पांच साल से बंद थी। उत्पादन दोबारा शुरू करने के साथ वैश्विक सप्लाय चेन को भी सक्रिय करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के कारण यह प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण हो गई थी।

एफ404-आईएन20 इंजन का तेजस कार्यक्रम से जुड़ाव एमके1ए के मौजूदा ऑर्डर से काफी पुराना है। इस इंजन को 2004 में तेजस के लिए चुना गया था और 2016 तक जीई एचएएल को 65 इंजन की आपूर्ति कर चुका था। अब एमके1ए कार्यक्रम के विस्तार के साथ इंजन की मांग भी बढ़ी है। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 97 अतिरिक्त एलसीए एमके1ए विमानों के लिए

62,370 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया था। इसमें 68 सिंगल-सीटर लड़ाकू विमान और 29 ट्विन-सीटर विमान शामिल हैं। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर छह वर्षों में पूरी की जानी है। विमानों में 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री रखने का लक्ष्य है। अप्रैल 2026 में भारत में एफ404-आईएन20 इंजन के लिए एक डिपो स्थापित करने की योजना भी सामने आई। इसका संचालन भारतीय वायुसेना करेगी, जबकि जीई तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, स्पेयर पार्ट्स और विशेष उपकरण उपलब्ध कराएगा। इससे तेजस बेड़े के रखरखाव और परिचालन उपलब्धता को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इंजन आपूर्ति में तेजी और स्थानीय रखरखाव क्षमता बढ़ने से भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ओडिशा: एसआई पेपर लीक मामले में ईडी ने की छापेमारी

हाईकोर्ट से 17 आरोपियों को इटका

भुवनेश्वर(ए)। ओडिशा में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के घरो और संबंधित ठिकानों पर सचन छापेमारी कर रही है, ताकि धन शोधन के पहलुओं और अनियमितताओं की गहराई से जांच की जा सके। यह कार्रवाई तब हो रही है जब हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट ने इस घोटाले में शामिल 17 आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इस बहुचर्चित मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।

आरोपियों को पिछले साल दिसंबर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और ओडिशा पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, जज ने टिप्पणी की थी कि आरोपी सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से लाखों रुपये लेकर प्रश्न पत्र लीक करने जैसे गंभीर अपराध में शामिल थे। इस तरह के कृत्यों से योग्य उम्मीदवारों का मनोबल टूटता है और भर्ती प्रक्रिया में जनता



का भरोसा कम होता है। न्यायमूर्ति सतपथी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि याचिकाकर्ताओं की कथित हकतों के कारण कंबाईड पुलिस से सर्विस एग्जामिनेशन 2024 को दो बार रद्द करना पड़ा। यह दशता है कि इस पेपर लीक ने न केवल हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य की भर्ती प्रणाली की अखंडता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। ओडिशा एसआई पेपर लीक केस में आरोपियों की सूची काफी लंबी है, जिसमें टी. अभिमन्यु डोरा, प्रियदर्शनी सामल, लोकनाथ साहू, श्रीकांत महाराणा, बिस्वजीत हरिचंदन, सागर कुमार गौड़ा, ताफिम अहमद खान, सुरेश चंद्र नायक, बिरंची कुमार नायक, निमाइन चरण साहू, अर्जुन नायक, बिस्वरंजन बेहरा, एंफेली सीताराम, राम बाबू

यादव, नीतीश कुमार, मुना मोहंती और अरविंद दास जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी पर भर्ती प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस बीच, ओडिशा में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इस साल अक्टूबर में इस पेपर लीक ने न केवल हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य की भर्ती प्रणाली की अखंडता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। ओडिशा एसआई पेपर लीक केस में आरोपियों की सूची काफी लंबी है, जिसमें टी. अभिमन्यु डोरा, प्रियदर्शनी सामल, लोकनाथ साहू, श्रीकांत महाराणा, बिस्वजीत हरिचंदन, सागर कुमार गौड़ा, ताफिम अहमद खान, सुरेश चंद्र नायक, बिरंची कुमार नायक, निमाइन चरण साहू, अर्जुन नायक, बिस्वरंजन बेहरा, एंफेली सीताराम, राम बाबू

एसआईआर विवाद: सीईसी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का महामोर्चा तैयार

नई दिल्ली(ए)। केंद्रीय चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। मतदाता सूची में विशेष एकीकृत संशोधन से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए, गठबंधन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का प्रयास करेगा। पिछले तीन दिनों से आक्रामक हो चुका यह प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक मोर्चे का रूप ले रहा है। विपक्ष का यह आक्रामक रुख एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। ये आपत्तियां मुख्य रूप से मतदाता सूची में पारदर्शिता और त्रुटियों से संबंधित थीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए गठबंधन के 10 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति भवन से अभी तक मुलाकात का कोई समय तय नहीं हुआ है। बड़े प्लान की तैयारी में जुटे गठबंधन के सांसद दोपहर 3 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक करेंगे, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी। विपक्षी सूत्रों ने कहा कि यदि राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिलता है, तो सभी विकल्प खुले हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के आवास जैसे संभावित स्थानों पर भी प्रदर्शन की योजना हो सकती है। इस मुहिम में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं, वहीं राहुल गांधी ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है।

